



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक १२]

गुरुवार, मार्च ७, २०२४/फाल्गुन १७, शके १९४५

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मार्च, २०२४.

क्रमांक जीवका-२०२३/प्र. क्र. ७१/नापु. २८.—ग्राहक बाबी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून असाधारण राजपत्र, भाग II-खण्ड ३ उप-खंड (ii) मध्ये दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, ८ फरवरी, २०२४.

का.आ. ५७५(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग II धारा-३, उप-धारा (ii) में दिनांक १२ जून, २०२३ के का. आ. स २५६६ (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, पैराग्राफ २ (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

२(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक ३१ मार्च, २०२४ तक की अवधि के लिए गेहूं :

(१)

- व्यापारी/थोक विक्रेता : ५०० टन
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए ५ टन।
- बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक आउटलेट के लिए ५ टन और उनके सभी डिपुओं पर ५०० टन
- प्रोसेसरस : मासिक स्थापित क्षमता का ६०% को अप्रैल, २०२४ के शेष महीनों से गुणा करके।

[ 'फा. मं. ३/१/२००७- नीति- III ]

**ऋचा शर्मा,**

अपर सचिव.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**  
**(Department of Food and Public Distribution)**

**Order**

**New Delhi, the 8th February, 2024.**

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the *Gazette of India, Extraordinary*, Part(II) Section-3, Sub-section(ii) *vide* number S.O. 2566(E) dated the 12th June, 2023, namely :—

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under :—

2(i) Wheat for a period up to 31st March 2024 with following stock limits for all States and Union Territories :

- Traders/Wholesalers : 500 MT
- Retailers : 5 MT for each Retail outlet
- Big Chain Retailers : 5 MT for each outlet and 500 MT at all their depot
- Processors : 60% of monthly installed capacity multiplied by remaining months till April 2024.

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

**RICHA SHARMA,**  
Addl. Secy.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**ता. मा. कोळेकर,**  
शासनाचे सहसचिव.